



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 24, 2019/आश्विन 2, 1941

No. 296]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 2019/ASVINA 2, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2019

[मामला सं. (ओ.आई.) – 16/2019]

विषय : चीन जनवादी गणराज्य, के मूल के अथवा वहां से निर्यातित रोल्स में फेस्ड ग्लास् वूल के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच ।

फा.सं. 6/23/2019-डीजीटीआर.—मै. यू.पी. टिवजा फाइबर ग्लास लिमिटेड (जिसे आगे आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटनरोधी शुल्क की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) से “रोल्स में फेस्ड ग्लास् वूल” (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या पीयूसी भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है ।

क. विचाराधीन उत्पाद

2. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद “रोल्स में फेस्ड ग्लास् वूल” है जिसे फाइबर ग्लास वूल (इंशुलेशन सामग्री) या रेजिन बॉन्डेड ग्लास वूल भी कहा जाता है ।

3. ग्लास बूल में फाइबर ग्लास फाइबर होता है जो बाइंडर से जुड़ा होता है ताकि कंबल और कैब/बोर्ड बनाए जा सकें। इस प्रक्रिया में ग्लास को फाइबराइजिंग मशीन से गुजारा जाता है और स्पिनर्स को घुमाकर केन्द्रीयकृत कार्य द्वारा स्पिनर्स से नियंत्रित तरीके में फाइबर निकाले जाते हैं, साथ ही बाइंडर का छिड़काव किया जाता है और उसके बाद रोल, कंबल आदि बनाने के लिए क्यूरिंग ओवन के जरिए निकाला जाता है।
4. ग्लास बूल में साधारण ग्लास निर्माण कच्ची सामग्री का प्रयोग होता है। इसमें विशेष रूप से सिलकासेंड, सोडा ऐश (सोडियम कार्बोनेट), फेल्डस्पार, डोलोमाइट, चूना पत्थर और बोरेक्स पैंटाहाइड्रेट होता है। अन्य प्रयुक्त सामग्री में रीसाइकल्ड ग्लास कूलैट और बॉट आउट शीट ग्लास कूलैट शामिल होता है। कच्ची सामग्री को बैच मिश्रण प्रक्रिया से मिलाया जाता है और उसके बाद विद्युत भट्टी/गैस भट्टी में एक साथ डाला जाता है, जहां इसे लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। भट्टी से स्ट्रीम निकाली जाती है और उसे फोरहर्क नामक कंडीशनर में डाला जाता है जहां ग्लास को उस तापमान तक पहुंचाया जाता है जब इसे फाइबरीकृत किया जा सके।
5. इस उत्पाद के प्रमुख उपयोग में धातु और कंक्रीट भवन के निर्माण में तापन, वेंटीलेशन और भवन को कूलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वातानुकूलन प्रणाली में होता है, इसका प्रयोग अकॉस्टिक अनुप्रयोगों, पोत निर्माण, रेलवे और ऑटोमोबाइल सहित परिवहन उद्योग में होता है। इस उत्पाद में अज्वलनशील और अग्नि सुरक्षित विशेषताओं के अलावा, सुपीरियर तापीय और अकॉस्टिक कार्य निष्पादन की अंतर्निहित मजबूती होती है। भवनों में इस उत्पाद के प्रयोग से उच्च ऊर्जा, कार्यकुशलता मिलती है और इस उत्पाद के प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए बढ़ रहे हैं।
6. संबद्ध उत्पाद को अध्याय शीर्ष 70 "ग्लास और ग्लासवेयर" के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। संबद्ध वस्तु को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के विभिन्न उप शीर्षों जैसे 7019 9010, 7019 9090, 7019 1900, 7019 3900, 7019 5900 आदि के अधीन आयात किया जा रहा है। किसी भी तरह से सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक प्रयोजन के लिए है और शुल्क लगाने और संग्रहण के लिए वस्तुओं का वर्णन लागू होगा।

ख. सामान वस्तु

7. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सामान वस्तु है। यह बताया गया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई खास अंतर नहीं है। आवेदक ने दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

8. यह आवेदन मै. यू पी ट्वीगा फाइबर ग्लास लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है जो देश में संबद्ध वस्तु के एकमात्र उत्पादक हैं और उसका कुल घरेलू उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा बनता है।
9. अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक के पास देश में कुल घरेलू उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा है। उन्होंने इस आशय के आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किए हैं कि उन्होंने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित हैं। अतः आवेदक को नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग माना जा सकता है। इसके अलावा, आवेदक नियम 5 (ख) के अधीन स्थिति संबंधी परीक्षण को भी पूरा करता है।

घ. उत्पाद नियंत्रण संख्याएं (पी सी एन)

10. आवेदक ने उत्पाद के विभिन्न किस्मों/रूपों की उचित तुलना के प्रयोजनार्थ उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पी सी एन) को अपनाने का प्रस्ताव किया है। आवेदक ने मोटाई, घनत्व और फेसिंग के प्रकार के आधार पर पी सी एन प्रणाली को अपनाने का प्रस्ताव किया है। आवेदक द्वारा सुझाई गई पी सी एन पद्धति नीचे दी गई है।
11. प्रस्तावित पी सी एन में पहले दो अंक उत्पाद के घनत्व को दर्शाते हैं (किलोग्राम/घन मीटर), अगले तीन अंक उत्पाद की मोटाई दर्शाते हैं (मि.मी. में), अगले दो अंक पहली फेसिंग के प्रकार को दर्शाते हैं और अंतिम दो अंक नीचे दिए गए

कोड के अनुसार दूसरी फेसिंग के प्रकार को दर्शाते हैं। यदि कोई दूसरी फेसिंग नहीं है तो हितबद्ध पक्षकार "00" का प्रयोग कर सकते हैं।

12. विभिन्न फेसिंग के लिए कोडिंग का निम्नानुसार प्रस्ताव किया गया है :—

फेसिंग के प्रकार	पीसीएन में संगत संख्या
एएलजी	01
बीजीसी	02
बीजीटी	03
डीएसएफएसके	04
एफजीटी	05
एफएसके	06
एमपीएफ	07
आर 3035 एचडी	08
डब्ल्यू एम पी -50	09
डब्ल्यू एम पी -बीआर	10
डब्ल्यू एम पी -बी आर प्लस	11
अन्य कोई	12
कोई नहीं (केवल दूसरी फेसिंग के मामले में)	00

13. प्रस्तावित पी सी एन प्रणाली के संबंध में कोई टिप्पणी इस जांच की शुरुआत की तारीख से 14 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

ड. शामिल देश

14. वर्तमान जांच चीन जन.गण. से कथित पाटित वस्तुओं के संबंध में है।

च. सामान्य मूल्य

15. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और उसने सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया है। उन्होंने बताया है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-8 के अनुसार चीन को यदि संबंधित फर्म/उत्पादक/निर्यातक पैरा 8 (3) में निर्धारित मापदंडों के आधार पर उक्त मान्यता का खंडन करने में सक्षम नहीं होते हैं तो उसे गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के सर्वाधिक दक्ष संयंत्र की सूचना/आंकड़ों पर विचार करते हुए पी सी एन वार सामान्य मूल्य की गणना की है।

छ. निर्यात कीमत

16. आवेदक ने डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर निर्यात मूल्य का दावा किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन संभलाई और निकासी प्रभार, बिक्री कमीशन आदि के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने पूर्व की जांच में ऐसे समायोजन पर अपनी सुसंगत प्रक्रिया के अनुसार निर्यात कीमत के समायोजन पर विचार किया है और डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों पर भी इसे लागू किया है।

ज. पाटन मार्जिन

17. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर निर्यात कीमत के साथ की गई है जिससे प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के संबंध में अत्यधिक पाटन मार्जिन का पता चलता है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे पता चलता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

झ. क्षति और कारणात्मक संबंध

18. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने पाटित आयातों की समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से बड़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री और लाभ, नियोजित पूंजी पर नकद लाभ और आय के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हो रही है जो पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराता है।

ट. पाटनरोधी जाँच की शुरुआत

19. और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जाँच की शुरुआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ठ. जाँच की अवधि (पी ओ ई)

20. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि अप्रैल, 2018-मार्च, 2019 तक की है। क्षति जाँच अवधि में 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 की अवधि और जाँच अवधि शामिल होगी। जाँच अवधि से बाद की अवधि पर भी संभावना विश्लेषण के प्रयोजनार्थ विचार किया जा सकता है।

ड. सूचना प्रस्तुत करना

21. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों व प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है।

निर्दिष्ट प्राधिकारी

व्यापार उपचार महानिदेशालय

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

ढ. समय सीमा

22. हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (दिनों 40) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास अपने उत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार "रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

ण. गोपनीय/अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

23. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।
24. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
25. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।
26. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/ रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
27. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
28. सभी हितबद्ध पक्षों को इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उनके उत्तर का अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है। ऐसा नहीं करने पर सूचना को हटाया जा सकता है या उत्तर को अस्वीकार किया जा सकता है। सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

त. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

29. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

थ. असहयोग

30. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th September, 2019

[Case No. (OI) 16/2019]**Subject: Anti-Dumping investigation concerning imports of Faced Glass Wool in Rolls originating in or exported from China PR.**

F. No. 6/23/2019-DGTR.—M/s U.P. Twiga Fiberglass Limited (hereinafter also referred to as the Applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for imposition of Anti-dumping duty on imports of “Faced Glass Wool in Rolls” (hereinafter also referred to as the subject goods or PUC) from China PR (hereinafter also referred to as the subject country).

A. Product under Consideration

2. The product under consideration for the purpose of present investigation is “Faced Glass Wool in Rolls” also referred as Fiberglass Wool (Insulation Material) or Resin Bonded Glass Wool.
3. Glass wool consists of fine glass fibers combined with binder to make blankets and slabs/boards. The process involves passing glass through a fiberizing machine and drawing fibers in a controlled manner from spinners by centrifugal action of rotating spinners, binder is sprayed simultaneously and then passed through curing oven to form rolls, blanket etc.
4. Glass wool uses common glass-making raw materials, typically consisting of Silica sand, soda ash (sodium carbonate), Feldspar, dolomite, limestone and Borax Penta hydrate. Other materials used are recycled glass cullet and bought out sheet glass cullet. The raw materials are mixed in a batch mixing process, then fed together into an electrical furnace/ gas furnace where it is heated to approximately 1500°C. The stream is tapped from furnace and is fed into a conditioner called forehearth where the glass is brought to a temperature where it can be fiberized.
5. The product finds major uses in construction of metal and concrete building, heating, ventilation and air conditioning system to provide cooling services to buildings, acoustic application, shipbuilding, transport industry including railways and automobiles. The product has inherent strength of superior thermal and acoustic performance in addition to non-combustible and fire safe properties. Buildings achieve high energy efficiency by using this product and applications of this product have been increasing for different purposes.
6. The subject products are classified under Chapter Heading 70 “Glass and glassware”. The subject goods are being imported under various sub-headings like 7019 9010, 7019 9090, 7019 1900, 7019 3900, 7019 5900 etc. of the Customs Tariff Act, 1975. In any case, the customs classification is for indicative purposes only and the description of goods shall prevail for the imposition and collection of duties.

B. Like Articles

7. The applicant has claimed that the goods produced by the domestic industry are like articles to the subject goods originating in or exported from subject country. It has been stated that there is no significant difference in the subject goods produced by the applicant and those exported from subject country. The applicant has claimed that the two are technically and commercially substitutable. For the purpose of present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as ‘like articles’ of the subject goods imported from subject country.

C. Domestic Industry & Standing

8. The application has been filed by M/s U.P. Twiga Fiberglass Limited who is the only producer of the subject goods in the country and accounts for 100% share in the total domestic production.
9. The Authority notes that the applicant holds 100% share in total domestic production in the country. They have also furnished necessary certifications to the effect that they have not imported the subject goods from the subject country nor are they related to any exporter or importer of the subject goods from the subject country. Therefore,

the applicant can be termed as eligible Domestic Industry in terms of the Rule 2(b). Further, the applicant also satisfies the test of standing under Rule 5(b).

D. Product Control Numbers (PCN)

10. The applicant has proposed adoption of Product Control Numbers (PCN) for the purpose of fair comparison between different types/forms of the product. Applicant has proposed the PCN system on the basis of thickness, density and the type of facing. The PCN methodology suggested by the applicant is provided below.
11. In the proposed PCN, first two digits represent the density of the product (in Kg/metre cube), next three digits represent the thickness of the product (in millimetres), next two digits represent the type of first facing and the last two digits represent the type of second facing as per the codes given below. If there is no second facing, the interested party may use "00".
12. The coding for the different facings is proposed as follows:

Type of Facing	Corresponding number in PCN
ALG	01
BGC	02
BGT	03
DSFSK	04
FGT	05
FSK	06
MPF	07
R3035 HD	08
WMP-50	09
WMP-VR	10
WMP-VR R Plus	11
Any other	12
None (only in case of second facing)	00

13. Any comments with regard to the proposed PCN system may be filed within 14 days from the date of initiation of this investigation.

E. Country Involved

14. The present investigation is in respect of alleged dumped goods from China PR.

F. Normal Value

15. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and has determined normal value in accordance with Paras 7 and 8 of Annexure I of the Rules. They have stated that in terms of Para 8 of Annexure I of the anti-dumping rules, China has to be presumed to be a Non-market Economy Country unless the concerned firms/producers/exporters are able to rebut the said presumption based on the criteria spelt out in Para 8(3). The domestic industry has constructed PCN-wise normal value taking into account the information/figures of the most efficient plant of the domestic industry.

G. Export Price

16. The Applicant has claimed the export price on the basis of transaction wise data by DGCI&S, Kolkata. Price adjustments have been claimed on account of estimated ocean freight, marine insurance, inland transportation, port handling and clearance charges, sales commission etc. The Authority has considered adjustments on export price as per its consistent practice on such adjustments in earlier investigations and applied the same on DGCIS data.

H. Dumping Margin

17. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie show significant dumping margin in respect of the subject goods from the subject country. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is higher than the ex-factory

export price, indicating that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

I. Injury and Causal link

18. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and also in relation to production and consumption in India, price undercutting, price suppression/depression, price underselling, profitability, cash profits and return on capital employed. There is sufficient prima facie evidence of injury being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from the subject country to justify initiation of an anti-dumping investigation.

J. Initiation of Anti-dumping Investigation

19. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country; and injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exists to justify initiation of an anti-dumping investigation, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

K. Period of Investigation (POI)

20. The period of investigation for the purpose of the present investigations is April 2018- March 2019. The injury investigation period shall cover the periods 2015-16, 2016-17, 2017-18 and the period of investigation. The period after the investigation period may also be considered for the purpose of likelihood analysis.

L. Submission of information

21. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building
5 Parliament Street, New Delhi -110001.

M. Time Limit

22. Interested Parties may file their responses with the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

N. Submission of Information on Confidential / Non-Confidential basis

23. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.
24. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (02) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.
25. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
26. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not

susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

27. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
28. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

O. Inspection of Public File

29. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

P. Non-cooperation

30. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Director General